Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 2 | November 2023 - April 2024 | pp. 65-68

'मोतियों की माला' बनाम 'हीरों का हार' : भारत-चीन गतिरोध

भावना नन्दवाना

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

21वीं सदी के इस युग में हिंद प्रशांत महासागर का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है जिसमे भी हिंद महासागर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि नाम से ही विदित है हिंद जो कि भारत के नाम पर रखा गया है इस क्षेत्र में भारत के सामरिक, रणनीतिक, आर्थिक महत्व को स्पष्ट करता है। अतः हिंद प्रशांत महासागर से में एकछत्र शक्ति बनने के लिए आवश्यक है कि हिंद महासागर में विद्यमान राष्ट्रों के साथ सुदृढ़ संबंध की स्थापना हो। इसी दिशा में चीन द्वारा हिंद महासागर में भारत के महत्व व भूमिका को कम करने के उद्देश्य से यहां विद्यमान राष्ट्रों के साथ आर्थिक व राजनीतिक संबंधों की स्थापना की जा रही है। इस हेतु वह बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान इत्यादि राष्ट्रों में बंदरगाह की स्थापना व निवेश कर रहा है जो कि निश्चित रूप से भारतीय हितों के दृष्टिकोण से सही नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि भारत द्वारा चीन को काउंटर किया जाए। अतः भारतीय विदेश नीति निर्माताओं द्वारा हिंद महासागर की तरह ही महत्व रखने वाले दक्षिण चीन सागर, पूर्वी सागर में अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से भारत द्वारा यहां विद्यमान राष्ट्रों के साथ आर्थिक सामरिक व राजनीतिक संबंधों की स्थापना की जा रही है। भारत चीन के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों की स्थापना कर चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स पॉलिसी' को प्रति संतुलित कर रहा है। भारत के द्वारा प्रशांत महासागर में चीन के विरुद्ध 'हीरो का हार' नीति को अपनाया जा रहा है, उसे हीरो का हार रणनीति का नाम दिया गया, इस शोध पत्र में इसी रणनीति का विश्लेषण किया गया है।

संकेताक्षर—*हिंद महासागर, प्रतिसंतुलन, रणनीति, दक्षिण चीन सागर, रणीतिक-सामरिक संबंध*

प्रस्तावना

वर्तमान में भारत द्वारा चीन के एशिया-प्रशांत महासागर में निरंतर बढ़ते सामरिक आर्थिक प्रभाव को रोकने के लिए चीन के चारों ओर का हार बना रहा है तथा इस हार में जापान मंगोलिया, वियतनाम, अमेरिका, आस्ट्रेलिया जैसे हीरे है। भारत का यह कदम चीन की भारत के विरुद्ध 'मोतियों की माला' के विरुद्ध जवाब है। चीन आज बहु-ध्रुवीय विश्व का पक्षधर है ऐसे में वह अमेरिकी प्रभुत्व को प्रत्येक क्षेत्र (आर्थिक तकनीकी, सामरिक व रणनीतिक) में चुनौती प्रस्तुत कर रहा है जो कि अमेरिकी जैसी महाशक्ति आसानी से सहन नहीं कर सकती है। अतः वह भी चीन के विरुद्ध भारत की 'हीरों का हार' नीति का समर्थन करता है। भारत की इस नीति को समझने से पूर्व हमें चीन की 'मोतियों की माला' नीति को समझना होगा। चीन की 'मोतियों की माला'(स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स पॉलिसी) नीति का जिक्र प्रथमतः अमरिकी रक्षा मंत्रालय द्वारा 2005 में "एशिया में ऊर्जा का भविष्य" नामक रिपोर्ट में किया था उपर्युक्त रिपोर्ट में चीन द्वारा हिन्द महासागर में अपने सामरिक अड्डे बनाये जाने का विवरण दिया गया था। यद्यपि चीन सदैव से ही इन सामरिक स्थानों का उपयोग अपने ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति का एक माध्यम बताता रहा है किन्तु इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन सामारिक स्थानों का प्रयोग सैन्य आवश्यकताओं के लिये किया जा

ISSN 2348-3857

सकता है। हिन्द महासागर में चीन द्वारा विकसित किये जा रहे इन सामरिक व रणनीतिक स्थानों को ही मोतियों संज्ञा दी गई है तथा इन मोतियों की भौगोलिक व रणनीतिक उपस्थिति इस प्रकार की है कि ये भारत को चारों तरफ से घेरे हुए है जिसे नीचे प्रस्तुत मानचित्र की सहायता से समझ सकते है।

आरेख 1 : चीन की 'मोतियों की माला' नीति

उपर्युक्त मानचित्र के सहयोग से स्पष्ट रूप से समझ सकते है चीन की 'मोतियों की माला' नीति भारत को हिन्द महासागर में चारों तरफ से घेरने की नीति है। दक्षिण चीन सागर में अवस्थित हैनान द्वीप चीन का पहला मोती है। इस द्वीप पर एयरबेस व सर्विलांस सिस्टम मौजूद है इसके सहयोग से चीन संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर निगरानी रखता है। अतः यह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीप है इसी दिशा में कंबोडिया व थाईलैण्ड जैसे आसियान राष्ट्रों में अपने सामरिक अड्डे बनाकर संपूर्ण दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है।

चीन भारत के पड़ोसी राष्ट्रों विशेषकर म्यांमार जिसके साथ भारत को बहुत लंबे समय तक राजनीतिक संबंध नहीं थे वहां अपना सामरिक प्रभाव स्थापित किया। चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है वही म्यांमार सैन्य शासन व्यवस्था वाला राष्ट्र है अतः दोनों के मध्य दीर्घकालीन राजनयिक संबंध नहीं थे जिसका फायदा चीन द्वारा उठाया गया। अतः चीन ने म्यांमार में भारी मात्रा में आर्थिक निवेश किया तथा म्यांमार के कोको द्वीप के आधुनिकीरण का कार्य भी कर रहा है सामरिक व रणनीतिक दृष्टि से यह द्वीप अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मात्र 35 किमी की दूरी पर है।

भारत के दूसरे पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका ने चीन द्वारा हम्बनटोटा बंदरगाह का निर्माण किया गया। हालांकि पूर्व में श्रीलंका द्वारा भारत से बंदरगाह विकसित करने के लिए कहा गया था इससे पहले कि भारत कोई निश्चय करता चीन ने श्रीलंका सरकार को बंदरगाह विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। बंदरगाह का निर्माण चीनी द्वारा व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ-साथ सैन्य दृष्टिकोण से भी किया गया है श्रीलंका में पनडुब्बियों का मिलना इस बात का प्रमाण है। चीन द्वारा भारत के पड़ोसी व मित्र राष्ट्र बांग्लादेश के प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह चिटगांव में एक कंटेनर का निर्माण किया गया हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत व बांग्लादेश के मध्य संबंधों में सुदृढ़ता देखने को मिली है तथापि दोनों राष्ट्रों के मध्य विद्यमान 'तिस्ता नदी जल विवाद, शरणार्थियों की समस्या, आंतकवाद जैसे तनावपूर्ण बिन्दुओं को शीघ्र-अतिशीघ्र सुलझाव की आवश्यकता है जिससे कि चीन हमारे रिश्ते की इन कमजारियों का फायदा ना उठा सके। भारत के निकटतम पड़ोसी व सदाबहार शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान में चीन का निरंतर हस्तक्षेप में बढ़ोतरी आसानी से देखी जा सकती है। चीन द्वारा अपनी 'वन बेल्ट वन रोड' नीति के तहत वह पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' का निर्माण कर रहा है तथा इसी नीति के तहत व ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। जो कि हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन का रणनीतिक प्रभाव बढ़ा देता है तथा कश्मीर मुद्दे व अनु. 370 के समाप्ति के विरुद्ध में यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को समर्थन देता है।

भारत की 'हीरों का हार' रणनीति

चूंकि चीन लगातार पिछले कुछ दशकों से हिन्द महासागर में अपनी 'ऋण जाल पॉलिसी' व 'मोतियों की माला' पॉलिसी के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन अपनी 'ऋण जाल' की नीति के तहत पहले राष्ट्रों को भारी मात्रा में ऋण उपलब्ध करवाता है तथा जब वे ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं होते है तो वह इन राष्ट्रों पर चीनी यू-सामरिक हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाता है, जैसे कि चीन जिबूती में अपने सैन्य अड्डे का मजबूतीकरण करके कर रहा है। चीन का इन्हीं सब नीतियों को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत ने भी चीन के पड़ोसी राष्ट्रों को साथ अपने संबंधों में सुधार ला रहा है तथा अपने नौसेनिक अड्डो में विस्तार कर रहा है भारत द्वारा स्थापित सामरिक ठिकाने स्थापित कर रहा है।

भारतीय सामरिक अड्डे

चंगाई नेवी बेस सिंगापुर—2018 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगापुर से एक सन्धि की है इस समझौते के

फलस्वरूप भारतीय नौसेना को इस समझौते के फलस्वरूप भारतीय नौसेना को इस आधार पर सीधे पहुँच की अवसर प्राप्त हुआ है तथा दक्षिण चीन सागर में जाने वाले भारतीय जहाजों के सिंगापुर बेस से ईंधन पुनर्भरण की सुविधा मिली है।

संबाग बंदरगाह, इण्डोनेशिया—2018 में ही भारत को सांबाग बंदरगाह तक सैन्य पहुँच मिली है तथा यह बंदरगाह मलक्का जलसन्धि के प्रवेश पर स्थित है तथा यह विश्व का प्रमुख चॉक पाइट है। चीनी व्यापार व कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी जलसन्धि से होकर गुजरता है।

दुक्म बंदरगाह ओमान—इण्डोनेशिया के सांबांग बदरगाह के बाद ओमान की दुक्म बंदरगाह ओमान सागर के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में अवस्थित हैं। यह बंदरगाह भारत को पर्शियन गल्फ से कच्चा तेल मंगवाने की सुविधा प्रदान करता है इसके साथ ही यह दो महत्वपूर्ण चीनी मोतियों जिबूती (अफ्रीका) ग्वादार (पाकिस्तान) के मध्य महत्वपूर्ण न्यू-सामरिक विस्थिति प्रदान करता है।

सिसली द्वीप—2015 भारत व सिसली इस क्षेत्र में नैवी अड्डे के निर्माण को लेकर आपस में सहमत हो गये तथा यह भारत को हिन्द महासागर क्षेत्र में सैन्य पहुँच प्रदान करता है। यह नेवी अड्डा भारत के लिए सामरिक रूप से काफी महत्व रखता है क्योंकि चीन लगातार अपनी समुद्री सिल्क मार्ग के जरिए अफ्रीका महाद्वीप में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।

चाबहार बंदरगाह—वर्ष 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री ने इस बंदरगाह को बनाने को लेकर सन्धि की थी यह बंदरगाह हमारी पहुंच अफगानिस्तान तक देता है। साथ ही यह हमें मध्य एशिया तक व्यापारिक मार्ग भी प्रदान करता है तथा पाकिस्तान में अवस्थित ग्वादर बंदरगाह के प्रतिसंतुलन के रूप में भी कार्य करता है। हालांकि इस वर्ष ईरान द्वारा इस बंदरगाह को विकसित करने का कार्य भारत से लेकर चीन को दे दिया है जो कि कहीं ना कहीं कूटनीतिक असफलता व चीन की 'मोतियों की माला' नीति में ओर अधिक सशक्त करता है अतः हमें हमारी वैदेशिक नीति व कूटनीतिक रणनीति में सुधार कर ईरान से पुनः रिश्ते सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि यह बंदरगाह हिन्द-महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

आरेख 2 : भारत के 'हीरों के हार' रणनीति

भारत के 'हीरों के हार' रणनीति को हम उपर्युक्त नक्शे के सहयोग से समझ सकते है, अभी तक हमने भारत द्वारा इस क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए स्थापित सामरिक अड्डों की बात की आगे हम भारत द्वारा इस क्षेत्र में स्थापित सामरिक संबंधों की बात करेंगे।

अश्गाबात समझौता व आई.एन.एस.टी.सी. (INSTC)

भारत वर्ष 2018 में 'मल्टी मॉडल ट्रॉसपोर्ट एग्रीमेट' में शामिल हुआ है जो कि भारत की पहुंच मध्य एशिया तक बढ़ाता है जिसमें कि तुर्केमिनिस्तन, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, जैसे राष्ट्र शामिल है तथा ये चीन के पश्चिमी पड़ोसी राष्ट्र है। पिछले कुछ वर्षों में भारत का मध्य एशिया राष्ट्र एक साथ व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि सभी 5 मध्य एशियाई राष्ट्रों की यात्रा की। अश्गाबात समझौता भारत को मध्य एशियाई क्षेत्र में भौतिक सम्बद्धता प्रदान करता है।

मंगोलिया—प्रधानमंत्री मोदी प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री है जिन्होंने कि मंगोलिया की यात्रा की जो कि चीन को एक संकेत भी है कि यदि दक्षिण एशिया में भारत को हराने की कोशिश करेगा तो भारत भी वह रणनीति अपना सकता है भारत व मंगोलिया दोनों राष्ट्र द्विपक्षीय एयर-कॉरिडार निर्माण को लेकर भी सहमत हुए जो कि मंगोलिया जैसे लैण्ड-लॉक देश की चीन पर निर्भरता को भी कम करेगा।

मध्य जापान—जापान चीन का उत्तरी-पूर्वी पड़ोसी राष्ट्र है। शीतयुद्ध के समय से ही जापान यूएस से जुड़ा हुआ है तथा पिछले एक दशक से प्रशांत महासागर में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत एक प्रमुख सामरिक भागीदार राष्ट्र है।

भारत व जापान द्वारा वर्ष 2014 में आपसी रिश्तों में और अधिक सुदृढ़ता लाने के लिए विशेष सामरिक व वैश्विक भागीदारी के मुद्दे पर सहमति जताई है। इसके अतिरिक्त दोनों राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2016 में 'सिविल न्यूक्लियर समझौते' पर हस्ताक्षर किये तथा यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि भारत यह प्रथम राष्ट्र जिसने 'नाभिकीय अप्रसार सन्धि' (NPT) पर सन्धि न करने के बावजूद जापान ने उसके साथ इस प्रकार का समझौता किया। दोनों राष्ट्र 'एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर' (AAGC) पर साथ मिलकर काम कर रहे है इस कॉरिडर को 'वन बेल्ट बन रोड कॉरिडोर' के प्रतिसंतुलन के रूप में देखा जा रहा उपर्युक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि जापान भारत का प्राकृतिक हीरा है।

वियतनाम—वियतनाम जापान का दक्षिण-पूर्वी पड़ोसी राष्ट्र है। प्रधानमंत्री मोदी की 2016 में यात्रा के पश्चात् दोनों राष्ट्रों के संबंधों में तेजी देखी जा सकती है। भारत व वियतनाम दोनों राष्ट्रों के संबंधों में तेजी देखी जा सकती है। भारत व एशिया क्षेत्र में मंगोलिया भारत के लिए एक उभरता हुआ हीरा साबित हो रहा है। वियतनाम दोनों राष्ट्र 2018 से संयुक्त नेवी अभ्यास कर रहे हैं। वियतनाम भारतीय सैटेलाइट मॉनिटिरिंग स्टेशन की शीघ्र ही शुरुआत होने वाली है भारत व वियतनाम दोनों राष्ट्र मिलकर दक्षिण चीन सागर में प्राकृतिक तेल संसाधनों की खोज में संयुक्त रूप से काम कर रहे है। अतः पिछले कुछ वर्षों में वियतनाम भारत के 'हीरों के हार' के हीरे के रूप में उभर चुका है।

उपर्युक्त सभी तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दूसरे राष्ट्रों के साथ बेहतर सामरिक सहयोग को स्थापित करने के लिए काफी कार्य किया है भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति अब 'बहुपक्षीय साझेदारी' में बदल चुकी है। साथ ही भारत मध्य एशियाई राष्ट्रों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए शीघ्रता से विभिन्न मार्गों पर काम कर रहा है व मध्य एशियाई राष्ट्र भी भारत के साथ जुड़ने व संबंध स्थापित करने में रुचिप्रद हैं। उनमें से कुछ राष्ट्र भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सहयोग भी कर रहे हैं। वहीं कुछ राष्ट्र क्षेत्र विशेष में शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

परिणामस्वरूप भारतीय विदेश नीति में एक नया बदलाव देखने को मिला है कि भारत चीनी परिक्षेत्र के सभी राष्ट्रों के साथ अच्छे दोस्ताना संबंध स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। यह भारत को सामरिक पहुंच भी प्रदान कर रहा है। चीन की भांति ही भारत द्वारा चीन को चारों ओर से हराने की नीति ही भारत का 'हीरों का हार' है।

निष्कर्ष

हम कह सकते हैं कि यदि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहता है तो उसे चीन के बढ़ते प्रभाव को निश्चित रूप से कम करना होगा। इस हेतु भारत को हिंद महासागर के साथ-साथ प्रशांत महासागर में विद्यमान अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों की मजबूती पर ध्यान देना होगा साथ ही जो राष्ट्र भारत की पकड़ से छूट रहे हैं यथा नेपाल, मालदीव, श्रीलंका इत्यादि के साथ संबंधों को एक बार पुनः मजबूत नवीनीकरण की आवश्यकता है। अतः हमारे हमारे विदेश नीति निर्माता द्वारा जो नवीन नीतियाँ यथा पड़ोसी पहल की नीति, पूर्व की और सक्रियता की नीति, यथार्थवाद की नीति, इत्यादि का पालन करते हुए अपने वैदेशिक संबंधों की स्थापना की जानी चाहिए साथ ही भारत द्वारा अपनी बढ़ती लोकप्रियता एवं नेतृत्वकर्ता की भूमिका का उपयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर अपने पहुंच में बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रीनिवासन, टीपी, काउंटरिंग अनादर स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स, द हिंदू, नई दिल्ली, 2014
2. राधाकृष्णन, आर.के., नॉट इन स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्सःश्रीलंका, द हिन्दू, नई दिल्ली, दिसंबर 2012
3. भाटिया, राजीव, अ विजन फॉर द इंडियन ओसियन, द हिंदू अगस्त, नई दिल्ली, 2016
4. चौधरी, रॉय, अदपांजन, चाइनाज बीआरआई नॉट दिल्ली, इंडो पेसिफिक विजन इन एन इनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी, द इकोनॉमिक टाइम्स, मुंबई, जून 2020
5. राजमोहन, सी., चाइनीज टेक अवे स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स, द इंडियन एक्सप्रेस, यूपी, जून 2014
6. कृष्णमूर्ति, जी., कॉमबेटिंग चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स, द इंडियन एक्सप्रेस, यूपी, दिसंबर 2016
7. अभी, अक्षय, स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स, इंडिया एंड द जियोपोलिटिक ऑफ चाइनीज फॉरेन पॉलिसी डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.ई.आईआर. इनफो
8. फ्रॉम डिफाइनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी तो रिगेन्ड रीजनल सुपरमेसी मोदी डॉक्ट्रिन इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.न्यूजभारती.कॉम
9. सेनगुप्ता, हिंडोल, इज इंडियाज नेकलेस ऑफ डायमंड कंप्लीट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.इंडियाडिफेन्स.इन